

योजना मंत्रालय

मांग संख्या 69

योजना मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2002-2003			संशोधित 2002-2003			बजट 2003-2004			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	15.71	30.43	46.14	17.73	30.10	47.83	48.21	30.56	78.77	
पूंजी	7.50	...	7.50	4.99	...	4.99	
जोड़	23.21	30.43	53.64	22.72	30.10	52.82	48.21	30.56	78.77	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	0.38	...	0.18	0.18	...	0.36	0.36	
2. योजना आयोग	3451	5.13	26.45	10.00	25.72	35.72	10.00	26.60	36.60	
3. राज्य मानव विकास रिपोर्ट के लिए यूएनडीपी सहायता	3475	0.65	...	1.87	...	1.87	3.00	...	3.00	
	3601	0.17	...	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	
	जोड़	0.82	...	1.97	...	1.97	3.10	...	3.10	
4. राष्ट्रीय जैव-डीजल मिशन	2406	25.00	...	25.00	
5. जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के देश स्तरीय आकलन के लिए डब्ल्यू.एच.ओ. सहायता	2215	0.06	...	0.06	...	0.06	
6. अन्य	3475	9.70	3.60	5.70	4.20	9.90	10.11	3.60	13.71	
	5475	7.50	...	4.99	...	4.99	
	जोड़	17.20	3.60	20.80	10.69	4.20	14.89	10.11	3.60	
कुल जोड़	23.21	30.43	53.64	22.72	30.10	52.82	48.21	30.56	78.77	
ख आयोजना परिव्यय*:-	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आ.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आ.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आ.ब. बा.सं.	जोड़
1. सचिवालय आर्थिक सेवा	13451	5.13	...	5.13	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
2. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	18.08	...	18.08	12.72	...	12.72	13.21	...	13.21
3. राष्ट्रीय जैव-डीजल मिशन	12406	25.00	...	25.00
जोड़	23.21	...	23.21	22.72	...	22.72	48.21	...	48.21	

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं:** इसमें योजना मंत्री और योजना राज्य मंत्री के सचिवालय के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

2. **योजना आयोग/योजना बोर्ड:** इस मद में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) सहित योजना आयोग के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

3. राज्य मानव संसाधन विकास रिपोर्ट तैयार करने के लिए यूएनडीपी सहायता की व्यवस्था की गई है।

4. **राष्ट्रीय जैव-डीजल मिशन:** इस नई स्कीम का अनुमोदन, जैव-ईंधनों के विभिन्न संभरण भंडारों, पेट्रोलियम और अन्य व्यूत्पादों का आयात घटाने के प्रयोजनार्थ अखाद्य तिलहनों के अर्क के साथ पेट्रोल/डीजल के सम्मिश्रण की उपलब्धता का अध्ययन करने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए किया गया है।

6. **अन्य:** (क) अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान (आईएएमआर), को सहायता अनुदान, जो भारत में मानव संसाधनों के स्वरूप, विशेषता तथा

उपयोग संबंधी जानकारी की प्रगति के लिए तथा सरकारी विभागों को जनशक्ति अनुसंधान सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है, (ख) विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं को प्रशिक्षण, अनुसंधान और संस्थाओं के विकास इत्यादि के लिए सहायता अनुदान, (ग) 'व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान' योजना के अंतर्गत भुगतान (घ) नरेला परिसर में आधारभूत ढांचे की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए 'आईएएमआर को सहायता-अनुदान' की आयोजना-स्कीम; (ङ) राष्ट्र विकास को प्रतिबिम्बित करने वाले सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक व्यापक आंकड़ा बैंक का निर्माण करने तथा राज्य विकास रिपोर्टें इत्यादि तैयार करने के लिए आयोजना हेतु 50वें वर्ष की पहल; (च) जनसंख्या संबंधी आयोग के लिए अनुदान सहायता प्रदान करना जिसे सरकार द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जनसंख्या संबंधी राष्ट्रीय आयोग के गठन के परिणामस्वरूप संशोधित अनुमान 2001-02 स्तर पर शुरु किया गया है।